PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Nai Dunia, New Delhi
Wednesday 14th January 2015, Page: 5
Width: 8.59 cms, Height: 15.46 cms, a4, Ref: pmin.2015-01-14.34.60

बस्तर का कोसा देता है डेढ़ किमी लंबा धागा

हेमंत कश्यप >> जगदलपुर

बस्तर के जंगलों में प्राकृतिक रूप से जन्म लेने वाला एक रैली कोसा डेढ़ किमी लंबा धागा देता है। इस खासियत के चलते ही बस्तर के कोसा की मांग पूरे देश में है। ऐसे ही रैली कोसा से धागा तैयार कर धरमपुरा और कालीपुर की 40 महिलाएं प्रति माह औसतन 6000 रुपए की आय प्राप्त कर रही हैं।

बस्तर का कोसा वस्त्र अपनी गुणवत्ता और रंग के कारण देश-विदेश में विख्यात है। प्रति वर्ष यहां के जंगलों से करीब 5 करोड़ नग कोसा फल एकत्र किया जाता है। ग्रामोद्योग विभाग के रेशम प्रभाग द्वारा धरमपुरा में गत 16 वर्षों से संचालित क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केंद्र के प्रभारी एसके विश्वकर्मा ने बताया कि एक साबूत रैली कोसा का वजन 2.5 ग्राम होता है। कास्टिक सोडा में उबालने के बाद वजन 1.6 ग्राम रह जाता है। उबले एक रैली कोसा से 15 सौ से लेकर 18 सौ मीटर अर्थात करीब डेढ़ किमी तक लंबा धागा निकाला जाता है। इस कारण ही बस्तर के रैली कोसा की मांग अधिक है।

जायसवाल ने बताया कि अनुसंधान केन्द्र में आसपास के गांवों की 40 महिलाएं प्रतिदिन पांच घंटा रैली कोसा से धागा निकालने आती हैं। यहां 20 महिलाएं मशीन से रिल्ड थ्रेड तो इतनी ही महिलाएं मटकी के पेंदें में रगड़ कर

गुणवत्ता और चमक के कारण देश में मांग अधिक

जगदलपुर। कोसा से निकलता धागा।

घिंचा धागा तैयार करती हैं। प्रत्येक महिला 25 दिनों में तीन-साढ़े तीन किग्रा कोसा धागा निकाल तथा केन्द्र को बेचकर औसतन छह हजार रुपए कमा लेती हैं। यह महिलाएं प्रति वर्ष करीब 600 किग्रा घिंचा और 450 किग्रा रिल्ड धागा तैयार कर लेती हैं। केंद्र में तैयार किया गया कोसा धागा जगदलपुर के कोसा सेन्टर के अलावा जांजगीर, चांपा, भागलपुर, कोटपाड़,आदि स्थानों को भेजा जाता है। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि बस्तर का कोसा हजारों संग्राहकों को रोजगार तो दे रहा है, यहां के बेरोजगार यदि कोसा वस्त्र बनाने का प्रशिक्षण लें तो स्थायी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, चूंकि कोसा वस्त्रों की मांग लगातार बढ़ रही है।

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Nai Dunia, New Delhi
Wednesday 14th January 2015, Page: 5
Width: 8.22 cms, Height: 5.14 cms, a4, Ref: pmin.2015-01-14.34.61

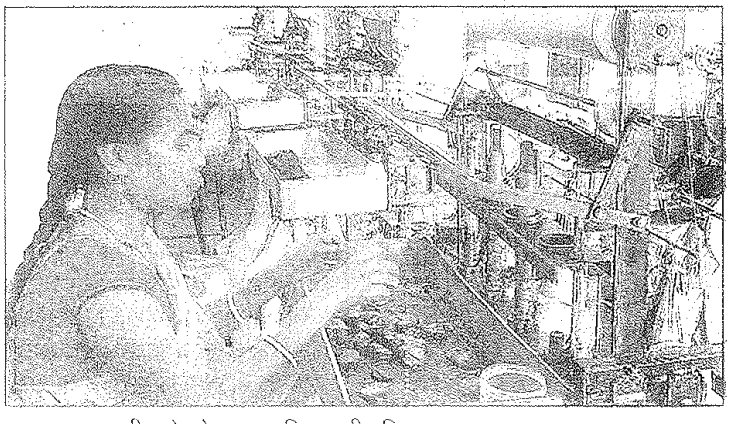

जगदलपुर। मशीन से कोसा धागा निकालती महिला।

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Pioneer, Delhi
Wednesday 14th January 2015, Page: 11
Width: 8.31 cms, Height: 18.75 cms, a4, Ref: pmin.2015-01-14.37.88

India-Vietnam trade may rise to $20 billion by 2020: Thanh

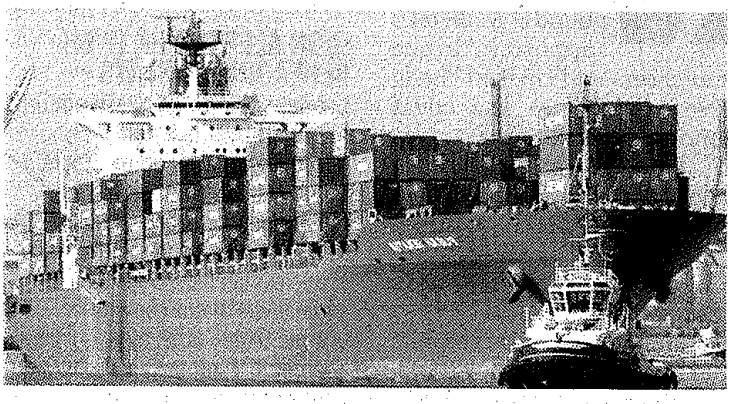

PNS ■ VADODARA

The bilateral trade between India and Vietnam is likely to touch $20 billion by 2020, country's ambassador to India Ton Sinh Thanh has said.

"The two-way trade between Vietnam and India is expected to reach $8 billion this year and could rise to $10 billion in 2015 and $20 billion by 2020," Thanh, who was in the city to meet members of the Exim Club Association of Exporters and Importers, told reporters here yesterday.

Vietnam is currently India's tenth largest trade partner.

Thanh is in Gujarat for the Vibrant Gujarat Global Investors Summit held in Gandhinagar.

"Vietnam's exports to India include electronics (mobile phones and components, computers and electronic hardware), natural rubber, chemicals, coffee and wood products. While Vietnam imports animal feed, corn, steel, pharmaceuticals and machinery from India," he said.

The ambassador thanked India for offering a $300 million line of credit for trade diversification and strengthening of commercial ties, hoping that it will enable Vietnam to import more polyester fabrics and yarns from India.

Currently, nearly half of Vietnam's imports of raw yarn and fabrics come from China. India's offer of a line of credit is aimed at diversifying Vietnam's source of materials and thus reduce its dependence on China.

Also, Indian companies will be allowed to have joint venture in Vietnam, the ambassador said.

Vietnam encourages Indian investment in areas of particular expertise such as infrastructure (railways), power generation and distribution, international bidding for projects in Vietnam, information technology, education, pharmaceutical research and production, and agro-products," Thanh said.

India ranks 30th on Vietnam's investment ladder. Figures for the number of projects financed by Indian direct investment vary from 69 to 84 as of September 2014.

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Jansatta, Delhi
Wednesday 14th January 2015, Page: 10
Width: 17.01 cms, Height: 7.78 cms, a4, Ref: pmin.2015-01-14.43.92

शरबती गेहूं और ग्वालियर के गलीचे की जीआई तमगे पर नजर

इंदौर,13 जनवरी(भाषा)। मध्यप्रदेश के मशहूर शरबती गेहूं और ग्वालियर के खूबसूरत गलीचे को वैश्विक ब्रांड में तब्दील करने के लिये इन्हें जीआइ प्रमाण पत्र दिलाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं।

दोनों उत्पादों के कारोबार से जुड़े लोगों को भौगोलिक संकेत :जियोग्राफिकल इंडिकेशनः का प्रमाणपत्र दिलाने में मदद का बीड़ा इंदौर के बौद्धिक संपदा सुगमता केंद्र (आइपीएफसी)ने उठाया है। इस इकाई को केंद्रीय सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)विकास मंत्रालय और भारतीय उद्योग महासंघ (सीआइआइ)ने मिलकर स्थापित किया है।

आइपीएफसी के कार्यकारी अधिकारी (बौद्धिक संपदा अधिकार) प्रफुल्ल निकम ने बताया- हम शरबती गेहूं और ग्वालियर के गलीचे को जीआइ प्रमाण पत्र दिलाने के बारे में इनके उत्पादकों और कारोबारियों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। हमने दोनों पारंपरिक उत्पादों के बारे में विस्तृत अध्ययन पहले ही शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जीआइ प्रमाण पत्र मिलने पर शरबती गेहूं और ग्वालियर का गलीचा वैश्विक ब्रांड बन जाएंगे। नतीजतन इनके पारंपरिक उत्पादकों और विक्रेताओं को न केवल सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा, बल्कि उन्हें दोनों उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री के मामले में पुख्ता कानूनी संरक्षण भी हासिल होगा।

निकम ने कहा- शरबती गेहूं और ग्वालियर के गलीचे को जीआइ प्रमाण पत्र मिलने के बाद इन पारंपरिक उत्पादों की नकल पर रोक लगेगी। मध्यप्रदेश की महेश्वरी साड़ियां, धार जिले की बाग प्रिंट, इंदौर में बनने वाले चमड़े के खिलौने और चंदेरी के परिधान उन प्रसिद्ध उत्पादों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरे बरसों में जीआइ प्रमाण पत्र मिल चुका है।

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rashtriya Sahara, Delhi
Wednesday 14th January 2015, Page: 10
Width: 24.66 cms, Height: 18.26 cms, a4r, Ref: pmin.2015-01-14.46.69

विकसित भारत का रोडमैप 'मेक इन इंडिया'

विश्लेषण

शशांक द्विवेदी

भारत को निवेश और मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने के सपने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ माह पहले 'मेक इन इंडिया' अभियान को लांच किया था। वाइब्रेंट गुजरात समिट पीएम मोदी के 'मेक इन इंडिया' प्रोजेक्ट का पहला टेस्ट है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून, अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोम्बे समेत लगभग 100 देशों के हजारों प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने भी शिरकत की और उन्होंने गुजरात में भारी निवेश की घोषणा भी की। यह भारत के लिए बहुत अहम सम्मेलन है जिसमें अमेरिका, कनाडा और जापान समेत आठ देशों ने पहली बार भागीदार देश के तौर पर हिस्सा लिया।

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में 'मेक इन इंडिया' एक बड़ा कदम है। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पड़ोसी देश चीन का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय बाजार भी चाइनीज उत्पादों से भरे पड़े हैं। ऐसे में 'मेक इन इंडिया' की अवधारणा को मजबूत करना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हो गया था। इस अभियान का मकसद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना है। अभियान का फोकस ऑटो, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल समेत 25 सेक्टरों को बढ़ाने पर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिए बगैर देश का विकास नहीं हो सकता है। सरकार इंडस्ट्री के रास्ते से सारी अड़चनें दूर करना चाहती है। एफडीआई की उन्होंने नई परिभाषा दे दी। उनकी नजर में भारतीयों के लिए एफडीआई का मतलब होना चाहिए 'फर्स्ट डेवलप इंडिया'। मेक इन इंडिया इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साथ ही इसकी मदद से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा।

भारत के 'मेक इन इंडिया' के लांच के बाद चीन ने एक बार फिर 'मेड इन चाइना' का नारा दिया है। ऐसे में भारत को चीन की मैन्युफैक्चरिंग को भी समझना होगा कि क्यों चीन

- मेक इंडिया इंडिया का एक मकसद देश में रोजगार के मौके पैदा करना भी है ताकि करोड़ों भारतीयों के लिए नई नौकरियों के अवसर खुलें। वाइब्रेंट गुजरात समिट प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'मेक इन इंडिया' का पहला बड़ा इम्तिहान है जिसमें 12 लाख करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की उम्मीद की जा रही है
- भारत में मेक इन इंडिया अभियान बरसों पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। देश में कारोबार और मैन्युफैक्चरिंग का माहौल बनते ही निश्चित ही भारत विकसित राष्ट्र का अपना सपना पूरा कर पाएगा

इस क्षेत्र में दुनिया में सबसे आगे है। चीन इंटरनेट और ई-कॉमर्स के जरिए अपनी इकोनॉमी को जोरदार रफ्तार देने का प्लान बना रहा है। चीन की तेज इकोनॉमिक ग्रोथ में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एसएमई) अहम भूमिका निभा रहे हैं। दरअसल, चीन के छोटे उद्यमियों ने नई तकनीक को अपनाकर न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चीन मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। शायद यही देखकर पिछले दिनों चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भारत ने चीन को टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया है। भारत के ज्यादातर स्मॉल एंटरप्राइजेज अभी भी तकनीक से दूर हैं। चीन दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। माइनिंग और प्रोसेसिंग के अलावा चीन कोल, मशीनरी, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, पेट्रोलियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, फुटवियर, ट्वायज, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट करता है। ग्लोबल रिसर्च फर्म मैकेंजी का मानना है कि वहां के एसएमई अब 'माइक्रो-मल्टीनैशनल' बन रहे हैं। पिछले 30 सालों में जोरदार औद्योगीकरण के दम पर चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया है। चीन की खासियतों में बड़ी संख्या में लेबर, सस्ती लागत और तुलनात्मक रूप से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। चीन ने न सिर्फ तेज रफ्तार से मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया, बल्कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर भी ध्यान दिया। मैकेंजी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के 21 फीसद स्मॉल एंटरप्राइजेज क्लाउड तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इंटरनेट एडॉप्शन रेशियो 25 फीसद तक है। जबकि भारत में यह बहुत कम है।

चीन ने न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया, बल्कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर भी खासा ध्यान दिया। इसमें नई तरह और बेहतरीन प्रोडक्टिविटी वाली मशीनों, लो कार्बन टेक्नोलॉजी, एनर्जी जैसे सेगमेंट शामिल हैं। इंटरनेट के जरिए चीन की एसएमई एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भी मजबूत हो रहे हैं। अलीबाबा या ग्लोबल सोर्सेज जैसे बी2बी मार्केटप्लेसेज के जरिए वे विदेशी कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेच रहे हैं। वहां के एसएमई अब 'माइक्रो-मल्टीनेशनल' बन रहे हैं, जबकि भारतीय एसएमई, खासकर सर्विस से जुड़े एंटरप्राइजेज को, सरकार की तरफ से मिलने वाले फायदे या इंसेंटिव नहीं मिल पाते। भारत की एसएमई के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से अलग-अलग स्कीमें तो चलाई जाती हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते वे उनका फायदा नहीं उठा पाते या भ्रष्टाचार के चलते ये फायदे उन तक पहुंच नहीं पाते। एसएमई को कर्ज मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, अब बैंकों ने एसएमई लोन पर फोकस करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहां एसएमई के लिए बैंक के अलावा वैकल्पिक व्यवस्था के कोई ठोस प्लान नहीं हैं। हाल में रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने भी बैंकों से एसएमई को आसान कर्ज मुहैया करवाने की बात कही है। फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, स्नैपडील जैसी कई ई-कॉमर्स कंपनियों ने एसएमई के लिए मार्केट प्लेस बनाए हैं, लेकिन उनकी छोटे कारोबारियों तक पहुंच धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। सरकार की तरफ से एसएमई को ई-रिटेलर्स के साथ जोड़ने का कोई सटीक प्लान भी नहीं है। इसके अलावा एसएमई को टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के जरिए ग्रोथ को रफ्तार देने हेतु बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें पर्याप्त पूंजी और प्रोडक्ट बेचने का डिजिटल जरिया सुलभ कराने के प्रयास होने चाहिए।

वाइब्रेंट गुजरात समिट का असली मकसद विदेशी कंपनियों को भारत में फैक्ट्री लगाने और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत निवेशकों की हर उलझन को दूर करने के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर निवेशकों को अपने सभी सवालों के जवाब सिर्फ 72 घंटों में मिलेंगे। इस अभियान के जरिए सरकार रेगुलेटरी प्रोसेस को आसान कर निवेश को प्रोत्साहित करेगी। नीति और नियमों के नाम पर जो अड़चनें आती हैं, सरकार ने इन्हें दूर करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया नाम का एक सेल भी बनाया है, जो उद्योग लगाने से लेकर रेगुलेटरी मंजूरी तक सभी मामलों में विदेशी निवेशकों की मदद करेगा। अभी तक नई कंपनी या नए व्यापार के लिए सरकारी लालफीताशाही आड़े आती थी, काफी वक्त लगता था किसी भी काम को शुरू करने में। लेकिन अब इन सब मुश्किलों को दूर करने की दिशा में बेहतर कदम उठाए गए हैं।

प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बजाय कॉरपोरेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देने की बात कही है। मेक इंडिया इंडिया का एक मकसद देश में रोजगार के मौके भी पैदा करना है ताकि करोड़ों भारतीयों के लिए नई नौकरियों के अवसर खुलें। वाइब्रेंट गुजरात समिट प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'मेक इन इंडिया' का पहला बड़ा इम्तिहान है जिसमें 12 लाख करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की उम्मीद की जा रही है। सच बात तो यह है कि भारत में मेक इन इंडिया अभियान बरसों पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। देश में कारोबार और मैन्युफैक्चरिंग का माहौल बनते ही भारत विकसित राष्ट्र का अपना सपना जरूर पूरा कर पाएगा।

(आलेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं)

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Line, Delhi
Wednesday 14th January 2015, Page: 4
Width: 8.30 cms, Height: 11.43 cms, a4, Ref: pmin.2015-01-14.54.33

Taiwan industry bodies sign three MoUs with Indian counterparts

OUR BUREAU

New Delhi, January 13

Three Taiwanese industry bodies on Tuesday signed separate memoranda of understanding (MoUs) with their counterparts in India. The three MoUs related to shipbuilding, electronics and textiles and were in addition to the three agreements signed at the Vibrant Gujarat 2015 summit.

While the Confederation of Indian Textile Industry (CITI) entered into a MoU with Taiwan Textile Federation, the Electric Lamp and Component Manufacturers' Association (ELCOMA) signed a MoU with Taiwan Electrical & Electronic Manufacturers' Association.

An MoU was also signed between Shipyards Association of India and Taiwan Shipbuilding Industry Association.

The MoUs are the beginning of new friendship between India and Taiwan and will provide the platform to expand the industrial collaboration between the two countries, said Shih-Chao Cho, Deputy Minister, Ministry of Economic Affairs of Taiwan. He lauded Prime Minister Narendra Modi's 'Make in India' and 'Digital India' initiatives.

"We can feel the determination of the Indian government to liberalise and deregulate to bring in investments", said Cho, who is leading a 50-member delegation from Taiwan

Rakesh Zutshi, Managing Director, Halonix Technologies, later told *BusinessLine* that Taiwan could play a role in providing LED technology to India and expanding its use here. On behalf of ELCOMA, Zutshi had exchanged the MoU with TEEMA.

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Line, Delhi
Wednesday 14th January 2015, Page: 17
Width: 4.18 cms, Height: 13.22 cms, a4, Ref: pmin.2015-01-14.54.127

Cotton body keeps output unchanged

OUR BUREAU

Coimbatore, January 13

Indian Cotton Federation (formerly South India Cotton Association) has maintained the cotton crop at its earlier estimate of 406 lakh bales for the 2014-15 season.

The Federation, according to its President J Thulasidharan reviewed the position last week after assessing the loss due to crop damage, water shortage and reports of low yield in certain pockets.

The Federation's assessment shows, that in the northern cotton belt comprising Punjab, Haryana and Rajasthan the yield would sustain at 54 lakh bales, while in the central zone comprising Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh, it would hover around 229 lakh bales and in the South at 115 lakh bales; Odisha and others would account for 8 lakh bales to take the total crop production estimate to 406 lakh bales.

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Bhaskar, Faridabad
Wednesday 14th January 2015, Page: 14
Width: 4.13 cms, Height: 6.62 cms, a4, Ref: pmin.2015-01-14.59.47

अमेरिका में बेहतरी से भारत का निर्यात बढ़ेगा

हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) तक कुल 17,926 करोड़ रुपए का हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट किया जा चुका है। पूरे वित्त वर्ष के लिए 27 हजार करोड़ रुपए का हैंडीक्राफ्ट निर्यात का टार्गेट है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट (ईपीसीएच) के चेयरमैन लेखराज महेश्वरी ने कहा कि आखिरी तिमाही में हम एक्सपोर्ट टार्गेट पूरा कर लेंगे। हमें अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं।